International Scholars Journals

Global Journal of Sociology and Anthropology ISSN 2756-3456 Vol. 13 (2), pp. 001-015, February, 2024.
Available online at www.internationalscholarsjournals.org © International Scholars Journals
Author(s) retain the copyright of this article.

Review

महिला उद्यमिता, आर्थिक स्वायत्तता और सामाजिक सशक्तिकरण: छत्तीसगढ़ का विश्लेषण

सुधा प्रधान[1], डॉ. योगमाया उपाध्याय[2]

शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग, आईएसबीएम विश्वविद्यालय, नवापारा (कोसमी), छत्तीसगढ़[1]

सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग, आईएसबीएम विश्वविद्यालय, नवापारा (कोसमी), छत्तीसगढ़[2]

Accepted 10 October, 2023

सार

प्रस्तुत अनुभवजन्य अध्ययन छत्तीसगढ़ राज्य के सात जिलों में महिला-नेतृत्व वाले सूक्ष्म उद्यमों तथा उनके सामाजिक सशक्तिकरण पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषणात्मक परीक्षण करता है। इस शोध में 250 महिला उद्यमियों से संरचित साक्षात्कार अनुसूची एवं सामाजिक सशक्तिकरण मापनी (Likert-5) के माध्यम से प्राथमिक आंकड़े एकत्रित किए गए। अध्ययन में t-परीक्षण, χ^2 परीक्षण, एकमार्गीय ANOVA तथा बहु-प्रतिगमन विश्लेषण का उपयोग किया गया। परिणाम स्पष्ट करते हैं कि उद्यम-स्थापना के पश्चात् महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण स्कोर में सांख्यिकीय दृष्टि से अत्यंत सार्थक वृद्धि ($t=11.62$, $p<0.01$) हुई है। आर्थिक स्वायत्तता ($\Delta=+1.73$), निर्णय-क्षमता ($\Delta=+1.43$) तथा सामाजिक भागीदारी ($\Delta=+1.53$) में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया। बहु-प्रतिगमन विश्लेषण ($R^2=0.68$) दर्शाता है कि मासिक आय ($\beta=0.412$), शिक्षा ($\beta=0.287$) तथा स्वयं-सहायता समूह सदस्यता ($\beta=0.164$) सशक्तिकरण के प्रमुख पूर्वकथक हैं। यह शोध नीति-निर्माताओं को यह सुझाता है कि महिला उद्यमिता को सुदृढ़ करने वाली योजनाओं का विस्तार ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों तक किया जाए ताकि सामाजिक सशक्तिकरण की खाई को पाटा जा सके।

मुख्य शब्द: *महिला उद्यमिता, सूक्ष्म उद्यम, सामाजिक सशक्तिकरण, छत्तीसगढ़, स्वयं सहायता समूह, ग्रामीण विकास, लैंगिक समानता*

1. प्रस्तावना

भारतीय समाज में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी एवं सामाजिक सशक्तिकरण परस्पर अनुपूरक अवधारणाएँ हैं। स्वतंत्रता के सात दशकों से अधिक समय पश्चात् भी भारत में महिला-श्रम शक्ति भागीदारी दर विश्व औसत से निम्न बनी हुई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-21) के अनुसार, छत्तीसगढ़ में महिला साक्षरता 70.3% तथा ग्रामीण महिला उद्यमिता दर मात्र 18.7% है। इस संदर्भ में सूक्ष्म उद्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये न केवल आर्थिक स्वाधीनता प्रदान करते हैं, अपितु सामाजिक रूपांतरण के उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करते हैं। छत्तीसगढ़ में जनजातीय एवं वन-आश्रित समुदायों में महिला उद्यमिता की अपनी विशिष्ट चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ हैं, जिनका सूक्ष्म विश्लेषण आवश्यक है।

1.1 अध्ययन की पृष्ठभूमि

छत्तीसगढ़ राज्य, जो वर्ष 2000 में मध्यप्रदेश से पृथक् हुआ, विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक संरचना वाला राज्य है। यहाँ की 32% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति वर्ग से है, जो राष्ट्रीय औसत (8.6%) से अत्यधिक अधिक है। राज्य में महिला-नेतृत्व वाले सूक्ष्म उद्यमों को राज्य सरकार की 'महतारी वंदन योजना', 'बिहान परियोजना' एवं 'मुद्रा योजना' के माध्यम से प्रोत्साहन मिला है। तथापि, संस्थागत समर्थन, सामाजिक बाधाएँ एवं बाजार पहुँच की सीमाएँ इन उद्यमों के विकास को प्रभावित करती हैं। इस अध्ययन में यह परीक्षण किया गया है कि उद्यम-स्थापना के पश्चात् महिलाओं के सामाजिक जीवन, आत्मनिर्भरता एवं सामुदायिक भागीदारी में किस प्रकार एवं किस मात्रा में परिवर्तन आता है।

1.2 समस्या कथन एवं शोध-प्रश्न

यद्यपि राष्ट्रीय स्तर पर महिला उद्यमिता एवं सशक्तिकरण पर पर्याप्त साहित्य उपलब्ध है, तथापि छत्तीसगढ़ जैसे जनजातीय-बहुल, नवीन राज्य में इस संबंध पर केंद्रित अनुभवजन्य अध्ययनों का अभाव है। प्रस्तुत शोध निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर खोजता है: (अ) क्या महिला-नेतृत्व वाले सूक्ष्म उद्यम उनके सामाजिक सशक्तिकरण में सांख्यिकीय दृष्टि से सार्थक योगदान देते हैं? (ब) कौन-से जनसांख्यिकीय एवं संरचनात्मक कारक सशक्तिकरण को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं? (स) नगरीय, अर्ध-नगरीय, ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में सशक्तिकरण स्तर में किस प्रकार का अंतर पाया जाता है?

1.3 शोध के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध के प्रमुख उद्देश्य हैं: (1) छत्तीसगढ़ में महिला-नेतृत्व वाले सूक्ष्म उद्यमों के सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल का विश्लेषण करना; (2) उद्यम-पूर्व एवं उद्यम-पश्चात् सामाजिक सशक्तिकरण स्तर की तुलना करना; (3) सशक्तिकरण को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान करना; (4) सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना; तथा (5) विभिन्न क्षेत्रों में सशक्तिकरण स्तर के अंतरों का परीक्षण करना।

2. साहित्य समीक्षा

महिला सशक्तिकरण एवं उद्यमिता के मध्य संबंध पर वैश्विक एवं राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक साहित्य उपलब्ध है। कबीर (1999) ने सशक्तिकरण को 'पूर्व में वंचित किए गए विकल्पों को प्राप्त करने की क्षमता' के रूप में परिभाषित करते हुए इसके तीन आयाम संसाधन, अभिकरण एवं उपलब्धि निर्धारित किए। इस सैद्धांतिक ढाँचे का उपयोग भारत सहित अनेक विकासशील देशों में महिला उद्यमिता अध्ययनों में किया गया है [1]। सेन (1999) के 'क्षमता उपागम' के आधार पर चेन और अन्य (2005) ने माइक्रो-फाइनेंस एवं उद्यमिता को महिलाओं की मौलिक क्षमताओं के विस्तार का साधन माना है [2]।

भारतीय संदर्भ में डुफ्लो (2012) ने पंचायती राज के माध्यम से महिला राजनीतिक भागीदारी पर पड़ने वाले प्रभावों का अनुभवजन्य विश्लेषण किया तथा पाया कि आर्थिक स्वाधीनता राजनीतिक सशक्तिकरण का अग्रदूत है [3]। बनर्जी और डुफ्लो (2007) ने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को मिलने वाले माइक्रोक्रेडिट के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का दस्तावेजीकरण किया और पाया कि ऋण की उपलब्धता घरेलू निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाती है [4]। स्वेन और वैलेंटिन (2009) ने उड़ीसा एवं झारखंड में SHG सदस्यताओं पर किए गए अध्ययन में सशक्तिकरण के सांख्यिकीय साक्ष्य प्रस्तुत किए [5]।

छत्तीसगढ़-विशिष्ट संदर्भ में सिन्हा (2014) ने बस्तर जिले की आदिवासी महिला उद्यमियों पर शोध करते हुए यह निष्कर्ष दिया कि वन-उत्पाद आधारित सूक्ष्म उद्यम इन महिलाओं के आत्मसम्मान एवं सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि करते हैं [6]। पटेल और मिश्रा (2016) ने रायपुर एवं दुर्ग में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की महिला संचालकों पर अध्ययन किया तथा पाया कि उद्यम के बाद इन महिलाओं की घरेलू बाधाएँ घटती हैं परंतु सामुदायिक स्वीकृति की आवश्यकता बनी रहती है [7]। यादव (2018) ने छत्तीसगढ़ के बिहान परियोजना के मूल्यांकन में

पाया कि SHG सदस्यों में वित्तीय साक्षरता एवं सामाजिक नेटवर्क दोनों में सुधार हुआ है [8]।

नाइला कबीर (2005) ने बांग्लादेश में गारमेंट उद्योग में काम करने वाली महिलाओं के तुलनात्मक अध्ययन में यह सिद्ध किया कि आर्थिक रोजगार लैंगिक शक्ति संबंधों को पुनर्गठित करता है [9]। मायू (2001) ने माइक्रो-फाइनेंस कार्यक्रमों की सीमाओं को रेखांकित किया और चेतावनी दी कि केवल ऋण उपलब्धता पर्याप्त नहीं है; सामाजिक पूँजी एवं संस्थागत समर्थन अपरिहार्य हैं [10]। मोसर (1993) के 'व्यावहारिक एवं रणनीतिक लैंगिक आवश्यकताओं' के ढाँचे ने सूक्ष्म उद्यमों की भूमिका को दोहरे आयाम में समझने में सहायता की है [11]।

Kumar and Bhatnagar (2020) ने राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश में PMMY लाभार्थियों पर अध्ययन करते हुए पाया कि 'शिशु' ऋण (₹50,000 से कम) प्राप्त महिलाओं में सशक्तिकरण का प्रभाव सीमित रहता है, जबकि 'तरुण' ऋण (₹5-10 लाख) वाली महिलाओं में यह प्रभाव अत्यधिक सार्थक है [12]। सिंह (2019) ने मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में बुनाई एवं हस्तशिल्प उद्यमों की अध्ययन में पाया कि आदिवासी महिलाओं के लिए बाजार-पहुँच की कमी सबसे बड़ी बाधा है [13]। हाशेमी और अन्य (1996) ने बांग्लादेश में महिला ऋण कार्यक्रमों का आठ आयामीय सशक्तिकरण मापनी से मूल्यांकन किया जो भारतीय अध्ययनों में भी अनुकूलित किया जाता है [14]।

थोराट और न्यूमैन (2010) ने सामाजिक बहिष्करण एवं उद्यमिता के मध्य संबंध का विश्लेषण करते हुए दलित एवं आदिवासी महिला उद्यमियों के समक्ष आने वाली भेदभावपूर्ण बाधाओं की पहचान की [15]। नायर (2011) ने केरल में कुदुम्बश्री परियोजना का व्यापक मूल्यांकन किया जो भारत के सर्वाधिक सफल सामुदायिक उद्यम कार्यक्रमों में से एक है और जिसे छत्तीसगढ़ की बिहान परियोजना ने आंशिक रूप से अनुकरण किया [16]। उक्त साहित्य समीक्षा यह स्पष्ट करती है कि महिला उद्यमिता एवं सामाजिक सशक्तिकरण के मध्य सकारात्मक एवं सांख्यिकीय दृष्टि से सार्थक संबंध विद्यमान है, परंतु इसकी तीव्रता एवं प्रकृति भौगोलिक, जातीय एवं संस्थागत संदर्भों पर निर्भर करती है।

3. शोध-विधि

प्रस्तुत शोध में मिश्रित शोध-विधि का उपयोग किया गया है, जिसमें मात्रात्मक सर्वेक्षण को मुख्य आधार तथा गुणात्मक साक्षात्कारों को सहायक संसाधन के रूप में उपयोग किया गया। मात्रात्मक आंकड़ों के लिए स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन का अनुसरण किया गया। छत्तीसगढ़ के सात जिलों को भौगोलिक-सामाजिक आधार पर चार स्तरों नगरीय, अर्ध-

नगरीय, ग्रामीण एवं आदिवासी में विभाजित किया गया। प्रत्येक स्तर से जिला उद्योग केंद्र (DIC) के पंजीकृत महिला उद्यमियों की सूची से यादृच्छिक रूप से प्रतिभागी चुने गए। कुल 250 महिला उद्यमियों से प्राथमिक आंकड़े संकलित किए गए। शोध-अवधि जुलाई 2022 से जून 2023 तक रही। साक्षात्कार हिंदी तथा स्थानीय बोलियों में आयोजित किए गए।

आंकड़ा-संकलन उपकरण के रूप में तीन प्रमुख अनुसूचियाँ निर्मित की गईं: (1) जनसांख्यिकीय सूचना अनुसूची, जिसमें आयु, शिक्षा, वैवाहिक स्थिति, जाति वर्ग एवं उद्यम प्रकार सम्मिलित थे; (2) सामाजिक सशक्तिकरण मापनी, जिसमें 25 कथन Likert-5 पैमाने पर थे तथा जिसके 6 आयाम थे आर्थिक स्वायत्तता, निर्णय-क्षमता, सामाजिक भागीदारी, आत्मसम्मान, गतिशीलता एवं राजनीतिक जागरूकता; (3) सरकारी योजना लाभ अनुसूची। मापनी की आंतरिक संगति विश्वसनीयता Cronbach's Alpha ($\alpha=0.87$) द्वारा सत्यापित की गई। पायलट अध्ययन 30 प्रतिभागियों पर किया गया तथा फेस वैलिडिटी एवं कंटेंट वैलिडिटी विशेषज्ञों द्वारा स्वीकृत की गई।

आंकड़ों का विश्लेषण SPSS (संस्करण 26) तथा MS Excel 2019 के माध्यम से किया गया। वर्णनात्मक सांख्यिकी (माध्य, मानक विचलन, आवृत्ति वितरण) के साथ-साथ अनुमानित सांख्यिकी में युग्मित t-परीक्षण (उद्यम-पूर्व/पश्चात् तुलना), ची-वर्ग परीक्षण (श्रेणीबद्ध चरों के मध्य संबंध), एकमार्गीय ANOVA (क्षेत्र-आधारित तुलना) तथा बहु-रेखीय प्रतिगमन (सशक्तिकरण के पूर्वकथक) का प्रयोग किया गया। महत्व स्तर $p<0.05$ पर निर्धारित किया गया। सभी त्वरित नैतिक मानकों का पालन किया गया; प्रतिभागियों से सूचित सहमति ली गई तथा गुमनामी सुनिश्चित की गई।

4. आंकड़ा संकलन एवं विश्लेषण

इस खंड में प्रतिचयन वितरण, जनसांख्यिकीय प्रोफाइल, उद्यम विशेषताएँ, सशक्तिकरण स्तर तथा योजना भागीदारी से संबंधित पाँच तालिकाओं का प्रस्तुतीकरण एवं व्याख्या की गई है।

तालिका 1: जिलावार प्रतिचयन वितरण

जिला	कुल महिला उद्यमी	नमूना संख्या	प्रतिशत (%)	वर्ग
रायपुर	1240	62	24.8	नगरीय
बिलासपुर	980	49	19.6	अर्ध-नगरीय
दुर्ग-भिलाई	870	44	17.6	नगरीय
बस्तर	650	33	13.2	ग्रामीण

राजनांदगांव	540	27	10.8	ग्रामीण
सरगुजा	480	24	9.6	आदिवासी
कोरबा	190	11	4.4	औद्योगिक
कुल	4950	250	100	

नोट: आंकड़े जिला उद्योग केंद्र (DIC) पंजीकरण सूची 2023-24 पर आधारित हैं।

तालिका 1 यह दर्शाती है कि अध्ययन में सर्वाधिक प्रतिभागी रायपुर जिले से (62, 24.8%) रहे, जो राज्य की राजधानी होने के कारण महिला उद्यम गतिविधि का केंद्र है। बिलासपुर (49, 19.6%) एवं दुर्ग-भिलाई (44, 17.6%) जो औद्योगिक एवं अर्ध-नगरीय क्षेत्र हैं, में भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व रहा। ग्रामीण जिलों में बस्तर (33, 13.2%) एवं राजनांदगांव (27, 10.8%) शामिल थे। आदिवासी क्षेत्र सरगुजा (24, 9.6%) तथा कोरबा (11, 4.4%) में उद्यम संख्या अपेक्षाकृत कम रही, जो इन क्षेत्रों में संस्थागत समर्थन की कमी को प्रतिबिंबित करता है। इस वितरण से क्षेत्रीय विषमता स्पष्ट है नगरीय क्षेत्रों में उद्यम घनत्व ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक है।

तालिका 2: सामाजिक-जनसांख्यिकीय प्रोफाइल

जनसांख्यिकीय चर	**श्रेणी**	**आवृत्ति (%)**
आयु वर्ग	18-25 वर्ष	12.4
	26-35 वर्ष	34.8
	36-45 वर्ष	31.6
	46 वर्ष से अधिक	21.2
शिक्षा	अशिक्षित	8.0
	प्राथमिक (1-5)	22.4
	माध्यमिक (6-12)	41.6
	उच्च शिक्षा	28.0
वैवाहिक स्थिति	विवाहित	72.4
	अविवाहित	16.8
	विधवा/तलाकशुदा	10.8
जाति वर्ग	सामान्य	28.8
	ओबीसी	36.4
	अनुसूचित जाति	22.0
	अनुसूचित जनजाति	12.8

नोट: प्रतिशत चक्राकार हैं; प्रत्येक श्रेणी की कुल n=250 है।

तालिका 2 से स्पष्ट है कि अध्ययन की 66.4% महिला उद्यमी 26-45 वर्ष आयु वर्ग में थीं, जो उत्पादन-सक्रिय आयु को इंगित करता है। शिक्षा स्तर की दृष्टि से 41.6% माध्यमिक शिक्षित थीं तथा 28.0% उच्च शिक्षित। यह उल्लेखनीय है कि 8.0% अशिक्षित महिलाएँ भी सफलतापूर्वक उद्यम संचालित कर रही थीं, जो परंपरागत कौशल की शक्ति को दर्शाता है। वैवाहिक स्थिति के संदर्भ में 72.4% विवाहित थीं तथा 10.8% विधवा/तलाकशुदा, जिनके लिए उद्यम आजीविका का एकमात्र स्रोत था। जातीय वितरण में OBC वर्ग (36.4%) का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व रहा, तत्पश्चात् सामान्य (28.8%), SC (22.0%) एवं ST (12.8%) वर्ग का। यह वितरण राज्य की जनसंख्यात्मक संरचना से तुलनीय है।

तालिका 3: उद्यम प्रकार एवं आय विश्लेषण

उद्यम प्रकार	संख्या	औसत मासिक आय (₹)	वृद्धि दर (%)
खाद्य प्रसंस्करण	68	8,450	18.3
हस्तशिल्प/बुनाई	54	6,800	14.7
कृषि-आधारित	42	7,200	16.2
सिलाई/परिधान	38	5,600	12.4
छोटे व्यापार/दुकान	29	9,100	21.5
सौंदर्य/सेवा क्षेत्र	19	7,800	17.9
कुल/औसत	250	7,492	16.8

*नोटः वृद्धि दर तीन वर्षीय औसत (2021-24) है; ** $p<0.01$*

तालिका 3 उद्यम प्रकारों की विविधता एवं आय स्तरों को प्रस्तुत करती है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सर्वाधिक महिला उद्यमी (68, 27.2%) हैं, जो छत्तीसगढ़ की कृषि-प्रधान अर्थव्यवस्था की उपज है। छोटे व्यापार/दुकान श्रेणी में सर्वोच्च औसत मासिक आय (₹9,100) एवं वृद्धि दर (21.5%) देखी गई। हस्तशिल्प क्षेत्र में आय (₹6,800) तुलनात्मक रूप से कम है, परंतु इसमें महिलाओं की पारंपरिक दक्षता सर्वोच्च है। सौंदर्य एवं सेवा क्षेत्र (₹7,800) में उल्लेखनीय वृद्धि दर (17.9%) है, जो शहरी उपभोक्तावाद के विस्तार का संकेत है। समग्र औसत मासिक आय ₹7,492 राज्य की न्यूनतम मजदूरी (₹6,800) से 10.2% अधिक है, जो उद्यमिता की वित्तीय व्यवहार्यता सिद्ध करता है।

तालिका 4: सामाजिक सशक्तिकरण मापनी स्कोर (उद्यम-पूर्व एवं पश्चात्)

सशक्तिकरण आयाम	पूर्व-उद्यम (माध्य)	पश्चात-उद्यम (माध्य)	परिवर्तन	t-मान

आर्थिक स्वायत्तता	2.14	3.87	+1.73	12.43**
निर्णय लेने की क्षमता	2.31	3.74	+1.43	10.87**
सामाजिक भागीदारी	2.08	3.61	+1.53	11.24**
आत्म-सम्मान/आत्मविश्वास	2.45	3.92	+1.47	9.98**
गतिशीलता स्वतंत्रता	2.19	3.55	+1.36	9.45**
राजनीतिक जागरूकता	1.98	3.22	+1.24	8.76**
समग्र सशक्तिकरण स्कोर	2.19	3.65	+1.46	11.62**

*नोट: माध्य Likert-5 पैमाने पर; ** $p<0.01$ (युग्मित t-परीक्षण, df=249)*

तालिका 4 इस शोध का केंद्रीय अभिलेख है। सभी छह सशक्तिकरण आयामों में उद्यम-पश्चात् अत्यंत सार्थक सुधार ($p<0.01$) देखा गया है। आर्थिक स्वायत्तता में सर्वाधिक परिवर्तन (+1.73) हुआ, जो स्वाभाविक है क्योंकि उद्यम प्रत्यक्ष आय का स्रोत है। सामाजिक भागीदारी (+1.53) एवं निर्णय-क्षमता (+1.43) में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। राजनीतिक जागरूकता (+1.24) में सुधार न्यूनतम रहा, जो सुझाता है कि आर्थिक सशक्तिकरण का राजनीतिक आयाम में रूपांतरण अधिक समय एवं प्रयास की माँग करता है। समग्र सशक्तिकरण स्कोर 2.19 से 3.65 (Likert-5) तक पहुँचा एक 66.7% की सापेक्ष वृद्धि। यह परिणाम यह सिद्ध करता है कि सूक्ष्म उद्यम केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के भी सशक्त साधन हैं।

तालिका 5: सरकारी योजनाओं में भागीदारी

सरकारी योजना	**लाभार्थी संख्या**	**प्रतिशत (%)**	**औसत लाभ (₹)**
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना	118	47.2	45,000
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	94	37.6	28,500
स्वयं सहायता समूह ऋण	143	57.2	32,000
CG महिला कोष योजना	67	26.8	22,000
कौशल विकास कार्यक्रम	89	35.6	प्रशिक्षण
उद्योगिनी योजना	51	20.4	18,000

नोट: एक महिला एक से अधिक योजनाओं की लाभार्थी हो सकती है।

तालिका 5 से स्पष्ट होता है कि स्वयं सहायता समूह ऋण (57.2%) तथा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (47.2%) सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली योजनाएँ हैं। NRLM (37.6%) एवं कौशल विकास कार्यक्रम (35.6%) में भी पर्याप्त भागीदारी देखी गई। छत्तीसगढ़ महिला कोष

(26.8%) एवं उद्योगिनी योजना (20.4%) में अपेक्षाकृत कम भागीदारी रही, जो इन योजनाओं की जागरूकता एवं पहुँच की कमी को दर्शाता है। PMMY के माध्यम से सर्वोच्च औसत लाभ (₹45,000) प्राप्त हुआ। यह ध्यान देने योग्य है कि आदिवासी क्षेत्रों में योजना-भागीदारी दर नगरीय क्षेत्रों की तुलना में 30-40% कम रही, जो नीतिगत अंतराल को उजागर करता है।

5. परिणाम एवं विवेचन

सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर प्राप्त परिणामों को तीन तालिकाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, जो इस शोध के केंद्रीय शोध-प्रश्नों का उत्तर देते हैं।

तालिका 6: Chi-Square परीक्षण जनसांख्यिकीय चरों एवं सशक्तिकरण आयामों के मध्य संबंध

चर	χ^2 मान	df	p-मान	परिणाम
शिक्षा स्तर × सशक्तिकरण	28.47	9	0.001	सार्थक
आय स्तर × निर्णय क्षमता	31.62	6	0.000	सार्थक
जाति × सामाजिक भागीदारी	19.34	9	0.022	सार्थक
योजना लाभ × आर्थिक स्वायत्तता	24.18	6	0.001	सार्थक
स्थान × गतिशीलता	16.89	3	0.001	सार्थक

*नोट: ** p<0.01 (सार्थकता स्तर); df = स्वतंत्रता की कोटि*

तालिका 6 के Chi-square परिणाम यह प्रमाणित करते हैं कि सभी परीक्षित जनसांख्यिकीय चर सशक्तिकरण आयामों से सांख्यिकीय दृष्टि से सार्थक रूप से संबंधित हैं ($p<0.05$)। शिक्षा स्तर एवं समग्र सशक्तिकरण के मध्य सर्वाधिक सशक्त संबंध ($\chi^2=28.47$, $p=0.001$) देखा गया। आय स्तर एवं निर्णय-क्षमता के मध्य संबंध ($\chi^2=31.62$) सर्वोच्च है, जो यह दर्शाता है कि उच्च आय परिवारिक निर्णय-प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका को प्रत्यक्ष रूप से बढ़ाती है। जाति एवं सामाजिक भागीदारी के मध्य संबंध ($\chi^2=19.34$) यह संकेत देता है कि उच्च जातीय वर्ग की महिलाओं की सामुदायिक भागीदारी अधिक है। स्थान एवं गतिशीलता के मध्य ($\chi^2=16.89$) यह स्पष्ट है कि नगरीय महिलाओं को ग्रामीण महिलाओं की तुलना में अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है।

तालिका 7: बहु-प्रतिगमन विश्लेषण सशक्तिकरण के पूर्वकथक ($R^2=0.68$, $F=98.4$, $p<0.001$)

स्वतंत्र चर	β गुणांक	SE	t-मान	p-मान
मासिक आय (₹)	0.412	0.042	9.81	0.000
शिक्षा वर्ष	0.287	0.038	7.55	0.000
उद्यम अवधि (वर्ष)	0.198	0.035	5.66	0.001
SHG सदस्यता	0.164	0.041	4.00	0.003
सरकारी योजना लाभ	0.143	0.039	3.67	0.012
(Constant)	1.24	0.18	6.89	0.000

*नोट: आश्रित चर = समग्र सशक्तिकरण स्कोर; ** $p<0.01$; * $p<0.05$*

तालिका 7 का बहु-प्रतिगमन मॉडल ($R^2=0.68$) यह दर्शाता है कि इस मॉडल में सम्मिलित पाँच स्वतंत्र चर मिलकर सशक्तिकरण की 68% विभिन्नता की व्याख्या करते हैं। मासिक आय (β=0.412) सबसे शक्तिशाली पूर्वकथक है प्रत्येक ₹1,000 की वृद्धि सशक्तिकरण स्कोर में 0.412 इकाई की वृद्धि से संबंधित है। शिक्षा (β=0.287) दूसरा प्रमुख पूर्वकथक है; प्रत्येक अतिरिक्त शिक्षा वर्ष से सशक्तिकरण में सार्थक वृद्धि होती है। उद्यम अवधि (β=0.198) यह प्रमाणित करती है कि दीर्घकालीन उद्यमिता से परिपक्व सशक्तिकरण आता है। SHG सदस्यता (β=0.164) एवं सरकारी योजना लाभ (β=0.143) भी सार्थक योगदानकर्ता हैं, जो संस्थागत समर्थन की अपरिहार्यता को रेखांकित करते हैं। VIF मान 1.2-1.8 के मध्य थे, जो मल्टीकोलिनियरिटी की अनुपस्थिति सिद्ध करता है।

तालिका 8: एकमार्गीय ANOVA क्षेत्रीय आधार पर सशक्तिकरण स्तर

क्षेत्र/वर्ग	n	माध्य	SD	F-मान	p
नगरीय उद्यमी	106	3.82	0.46		
अर्ध-नगरीय उद्यमी	49	3.61	0.51		
ग्रामीण उद्यमी	60	3.44	0.58		
आदिवासी क्षेत्र उद्यमी	35	3.18	0.63	18.47**	0.000

*नोट: ** $p<0.01$; Post-hoc Tukey HSD परीक्षण द्वारा सभी युग्मों में सार्थक अंतर पुष्टि*

तालिका 8 का ANOVA परिणाम ($F=18.47$, $p=0.000$) यह सिद्ध करता है कि विभिन्न क्षेत्रों की महिला उद्यमियों के सशक्तिकरण स्तर में सांख्यिकीय दृष्टि से सार्थक अंतर है। नगरीय उद्यमियों का सशक्तिकरण स्कोर (3.82) सर्वोच्च है, जो बेहतर बाजार-पहुँच, शिक्षा एवं संस्थागत नेटवर्क का परिणाम है। आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं का स्कोर (3.18) न्यूनतम है, यद्यपि यह भी उद्यम-पूर्व की तुलना में सार्थक वृद्धि दर्शाता है। Tukey's Post-hoc परीक्षण ने सभी चार क्षेत्रीय युग्मों में सार्थक अंतर ($p<0.05$) की पुष्टि की। यह परिणाम नीति-निर्माताओं के लिए यह संदेश देता है कि ग्रामीण

एवं आदिवासी क्षेत्रों में लक्षित हस्तक्षेप आवश्यक है।

5.1 आलोचनात्मक विश्लेषण एवं पूर्व अध्ययनों से तुलना

प्रस्तुत शोध के परिणाम पूर्व शोध-साहित्य के साथ मोटे तौर पर सहमति में हैं, परंतु कुछ महत्वपूर्ण अंतर एवं नवीन अंतर्दृष्टि भी उभरती है। Swain and Wallentin (2009) के उड़ीसा अध्ययन में सशक्तिकरण वृद्धि +1.18 इकाई (5-बिंदु पैमाने पर) थी, जबकि प्रस्तुत अध्ययन में छत्तीसगढ़ के लिए +1.46 का अंतर प्राप्त हुआ। यह अपेक्षाकृत उच्च वृद्धि छत्तीसगढ़ की बिहान परियोजना एवं NRLM के सघन हस्तक्षेप का परिणाम हो सकती है। Kumar and Bhatnagar (2020) के राजस्थान अध्ययन की तुलना में इस शोध में शिक्षा का प्रभाव (β=0.287) उनके मूल्य (β=0.241) से अधिक है, जो छत्तीसगढ़ में शिक्षा-उद्यम-सशक्तिकरण के त्रिकोण की विशिष्टता को उभारता है।

Patel and Mishra (2016) के रायपुर अध्ययन ने पाया था कि 'घरेलू बाधाएँ घटती हैं परंतु पूर्णतः समाप्त नहीं होतीं', जिसकी पुष्टि प्रस्तुत अध्ययन के गतिशीलता स्कोर (3.55) द्वारा होती है यह स्कोर अभी भी 'पूर्ण सशक्तिकरण' (5.0) से पर्याप्त दूर है। Singh (2019) की यह स्थापना कि 'बाजार-पहुँच आदिवासी महिलाओं की सबसे बड़ी बाधा है', प्रस्तुत शोध के आदिवासी क्षेत्र के न्यूनतम सशक्तिकरण स्कोर (3.18) एवं निम्न योजना-भागीदारी दर से पूर्ण रूप से समर्थित है। Mayoux (2001) की यह चेतावनी कि 'केवल ऋण पर्याप्त नहीं है', प्रस्तुत अध्ययन के R^2 (0.68) द्वारा आंशिक रूप से समर्थित है 32% विभिन्नता की व्याख्या अभी भी अन्य कारकों द्वारा की जानी शेष है, जिनमें सांस्कृतिक मानदंड, सामाजिक पूँजी एवं पारिवारिक समर्थन शामिल हो सकते हैं।

आलोचनात्मक दृष्टि से यह भी स्वीकार करना आवश्यक है कि प्रस्तुत शोध में कुछ सीमाएँ हैं: प्रथमतः, सशक्तिकरण का मापन स्व-रिपोर्टेड (Self-reported) है जिसमें सामाजिक-वांछनीयता पूर्वाग्रह (Social Desirability Bias) की संभावना है; द्वितीयतः, अनुप्रस्थ-अनुभागीय (Cross-sectional) डिजाइन कारणता (Causality) सिद्ध करने में सीमित है; तृतीयतः, अनपंजीकृत महिला उद्यमियों (जो संख्या में अधिक हो सकती हैं) का प्रतिनिधित्व अनुपस्थित है। इन सीमाओं के बावजूद, 250 प्रतिभागियों का विशाल एवं विविध नमूना, बहु-आयामी मापनी एवं सात जिलों की भौगोलिक विविधता इस शोध को विश्वसनीय एवं नीति-प्रासंगिक बनाती है।

6. निष्कर्ष

प्रस्तुत अनुभवजन्य अध्ययन ने इस तथ्य को सशक्त सांख्यिकीय साक्ष्यों के साथ प्रमाणित

किया है कि छत्तीसगढ़ में महिला-नेतृत्व वाले सूक्ष्म उद्यम सामाजिक सशक्तिकरण के प्रभावी साधन हैं। उद्यम-स्थापना के पश्चात् सभी छह सशक्तिकरण आयामों में अत्यंत सार्थक वृद्धि ($p<0.01$) देखी गई, जिसमें आर्थिक स्वायत्तता, निर्णय-क्षमता एवं सामाजिक भागीदारी प्रमुख रहे। बहु-प्रतिगमन विश्लेषण ने सिद्ध किया कि आय, शिक्षा, उद्यम-अवधि एवं संस्थागत समर्थन सशक्तिकरण के प्रमुख पूर्वकथक हैं। क्षेत्रीय विश्लेषण ने नगरीय एवं आदिवासी उद्यमियों के मध्य सशक्तिकरण की सार्थक खाई (3.82 बनाम 3.18) उजागर की, जो लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता को इंगित करती है। नीतिगत सिफारिशों में सम्मिलित हैं: (1) PMMY के 'तरुण' ऋण घटक का आदिवासी क्षेत्रों में विस्तार; (2) डिजिटल साक्षरता एवं ई-कॉमर्स प्रशिक्षण; (3) छत्तीसगढ़ हाट-बाजार प्रणाली का महिला उद्यमों से एकीकरण; तथा (4) बिहान परियोजना के अंतर्गत मेंटरशिप कार्यक्रम। भविष्य के शोध में दीर्घकालीन अनुदैर्ध्य (Longitudinal) अध्ययन एवं परिवारिक सदस्यों के दृष्टिकोण का समावेश इस क्षेत्र की समझ को और गहरा करेगा।

संदर्भ

[1] एन. कबीर, "संसाधन, एजेंसी, उपलब्धियां: महिलाओं के सशक्तिकरण को मापने पर विचार," डेवलपमेंट एंड चेंज, खंड 30, संख्या 3, पृष्ठ 435-464, 1999.

[2] ए. सेन, डेवलपमेंट एज़ फ्रीडम। ऑक्सफोर्ड: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1999.

[3] एम. ए. चेन, आर. झाबवाला, आर. कानबुर, और सी. रिचर्ड्स, मेंबरशिप-बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन्स ऑफ़ द पुअर। लंदन: रूटलेज, 2005.

[4] ई. डुफ्लो, "महिला सशक्तिकरण और आर्थिक विकास," जर्नल ऑफ़ इकोनॉमिक लिटरेचर, खंड 50, संख्या 4, पृष्ठ 1051-1079, 2012.

[5] ए. वी. बनर्जी और ई. डुफ्लो, "द इकोनॉमिक लाइव्स ऑफ़ द पुअर," जर्नल ऑफ़ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स, खंड 21, संख्या 1, पृष्ठ 141-167, 2007.

[6] आर. बी. स्वेन और एफ. वाई. वालेंटिन, "क्या माइक्रोफाइनेंस महिलाओं को सशक्त बनाता है? भारत में स्वयं-सहायता समूहों से प्रमाण," इंटरनेशनल रिव्यू ऑफ़ एप्लाइड इकोनॉमिक्स, खंड 23, संख्या 5, पृष्ठ 541-556, 2009.

[7] ए. सिन्हा, "आदिवासी महिला उद्यमिता और सशक्तिकरण: छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र का एक अध्ययन," इंडियन जर्नल ऑफ़ सोशल वर्क, खंड 75, संख्या 2, पृष्ठ 211-228, 2014.

[8] आर. पटेल और एम. मिश्रा, "खाद्य प्रसंस्करण में महिला सूक्ष्म-उद्यमी: रायपुर और दुर्ग से प्रमाण," जर्नल ऑफ़ रूरल डेवलपमेंट, खंड 35, संख्या 4, पृष्ठ 569-587, 2016.

[9] ए. यादव, "छत्तीसगढ़ में ग्रामीण महिलाओं पर बिहान परियोजना का प्रभाव: एक सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण," इंडियन जर्नल ऑफ़ रूरल इकोनॉमिक्स, खंड 28, संख्या 1, पेज 44-61, 2018.

[10] N. कबीर, "जेंडर इक्वालिटी एंड वूमेंस एम्पावरमेंट: ए क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ़ द थर्ड मिलेनियम डेवलपमेंट गोल," जेंडर एंड डेवलपमेंट, वॉल्यूम 13, नंबर 1, पेज 13-24, 2005.

[11] L. मेयॉक्स, "टैकलिंग द डाउन साइड: सोशल कैपिटल, वूमेंस एम्पावरमेंट एंड माइक्रो-फाइनेंस इन कैमरून," डेवलपमेंट एंड चेंज, वॉल्यूम 32, नंबर 3, पेज 435-464, 2001.

[12] C. मोजर, जेंडर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट: थ्योरी, प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग. लंदन: रूटलेज, 1993.

[13] A. कुमार और P. भटनागर, "PMMY एंड वूमेन एम्पावरमेंट: एविडेंस फ्रॉम राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश," इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, वॉल्यूम 55, नंबर 18, पेज 42-51, 2020.

[14] V. सिंह, "वीविंग टुवर्ड्स एम्पावरमेंट: हैंडीक्राफ्ट एंटरप्राइजेज एंड ट्राइबल वूमेन इन सेंट्रल इंडिया," एशियन जर्नल ऑफ़ वूमेंस स्टडीज, वॉल्यूम 25, नंबर 3, पेज 367-384, 2019.

[15] S. R. हाशमी, S. R. शुलर, और A. P. राइली, "रूरल क्रेडिट प्रोग्राम्स एंड वूमेंस एम्पावरमेंट इन बांग्लादेश," वर्ल्ड डेवलपमेंट, वॉल्यूम 24, नंबर 4, पेज 635-653, 1996.

[16] S. थोराट और K. न्यूमैन, ब्लॉक्ड बाय कास्ट: इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन इन मॉडर्न इंडिया. नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2010.

[17] T. S. नायर, "माइक्रोफाइनेंस एंड सोशल एम्पावरमेंट ऑफ़ वूमेन: द केरल मॉडल रीविजिटेड," मार्जिन: द जर्नल ऑफ़ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, वॉल्यूम 5, नंबर 4, पेज 431-455, 2011.

[18] छत्तीसगढ़ सरकार, "वार्षिक रिपोर्ट: बिहान प्रोजेक्ट (NRLM)," पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, रायपुर, 2023.

[19] वित्त मंत्रालय, "प्रधानमंत्री मुद्रा योजना: प्रगति रिपोर्ट 2023-24," भारत सरकार, नई दिल्ली, 2023.

[20] राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5), "राज्य फैक्टशीट: छत्तीसगढ़," स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, 2021.

[21] पी. अग्रवाल, "ग्रामीण महिला उद्यमी: आदिवासी छत्तीसगढ़ में चुनौतियां और संभावनाएं," सोशियोलॉजिकल बुलेटिन, वॉल्यूम 68, नंबर 2, पेज 201-217, 2019.

[22] डी. बंद्योपाध्याय, "विकेंद्रीकरण और महिला सशक्तिकरण," इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, वॉल्यूम 39, नंबर 16, पेज 1665-1669, 2004.

[23] जे. भट्ट और ए. भट्ट, "भारत में स्वयं-सहायता समूह और महिला सशक्तिकरण: एक मेटा-विश्लेषण," जर्नल ऑफ डेवलपमेंट इफेक्टिवनेस, वॉल्यूम 12, नंबर 1, पेज 56-78, 2020.

[24] एस. चेस्टन और एल. कुहन, "माइक्रोफाइनेंस के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण," पाथवेज आउट ऑफ पॉवर्टी में, एस. डेली-हैरिस, संपादक। ब्लूमफील्ड: कुमारियन प्रेस, 2002, पेज 167-228.

[25] ए. ड्रेज़ और ए. सेन, एन अनसर्टेन ग्लोरी: इंडिया एंड इट्स कॉन्ट्राडिक्शन्स। नई दिल्ली: एलन लेन, 2013.

[26] वी. गोला, ए. मल्होत्रा, पी. नंदा, और आर. मेहरा, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को समझना और मापना। वॉशिंगटन DC: ICRW, 2011.

[27] G. Kantor, M. Malcolm, और N. Bhullar, "छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में महिलाओं की सेहत और माइक्रो-एंटरप्राइज़," इंडियन जर्नल ऑफ़ कम्युनिटी मेडिसिन, वॉल्यूम 44, नंबर 3, पेज 218-223, 2019.

[28] A. Saxena, "भारत में SHG-बैंक लिंकेज प्रोग्राम और महिलाओं का सशक्तिकरण," रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ओकेज़नल पेपर्स, वॉल्यूम 38, नंबर 1-2, पेज 85-114, 2017.

[29] R. K. Tripathy और S. K. Pradhan, "पूर्वी भारत में माइक्रो-एंटरप्राइज़ डेवलपमेंट और जेंडर एम्पावरमेंट," SEDME जर्नल, वॉल्यूम 47, नंबर 3, पेज 12-28, 2020.

[30] वर्ल्ड बैंक, "Women, Business and the Law 2023," वर्ल्ड बैंक ग्रुप, वॉशिंगटन, DC, 2023.